

service will be equivalent to 50% of the average pensionable salary of the last 12 months. The minimum amount of the family pension is Rs. 450/- P.M. and the maximum may go upto Rs. 2500/- P.M. In addition, there is also a provision for payment of pension to two children subject to the minimum of Rs. 115/- P.M. per child.

(b) The contribution of the Central Government towards the Scheme has been fixed @ 1.16% of the wage of the subscriber.

सुपर बाजार में सेवा नियमों का उल्लंघन

713. श्री गोविन्दराम मिरी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारी सरकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए सुपर बाजार के बिक्री विभाग में पांच वर्ष से अधिक समय से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या कुछ बिक्री सहायकों ने प्रबंधन समिति के इस पक्षपातपूर्ण रवैए पर अपनी आपत्ति जताई है,

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारी/बिक्री सहायक 3 से 4 वर्ष के भीतर ही पदोन्नत हो गए जबकि अन्य को अपनी पदोन्नति के लिए 7 से 17 वर्षों तक से भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) जी, नहीं । सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि रिक्तियों और आवश्यकताओं के आधार पर बिक्री-सहायकों की समय-समय पर पदोन्नति की जाती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Request for additional allocation of Rice and Kerosene by Tamil Nadu

714. DR. D. MASTAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Tamil Nadu have asked for additional allocation of rice and kerosene for distribution in tribal and hilly regions of the State;

(b) if so, whether the request has been acceded to; and

(c) if not, the reasons therefor;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) No, Sir. There has been no such specific request from the Government of Tamil Nadu.

(b) and (c) The Government of Tamil Nadu had. requested for increase in the allocation of rice -for the Public Distribution System (PDS) to 1.60 lakh tonnes per month from 1.25 lakh tonnes per month, due to shortfall in paddy cultivation in the Cauvery Delta Area. Central Government has increased the monthly allocation of rice to Tamil Nadu to 1.40 lakh tonnes per month, on an ad hoc basis, for a period of four months from November, 1995.

Government of Tamil Nadu have also sought an ad hoc allocation of 10000 kilo litres of kerosene for the PDS, over and above their normal allocation on account of floods and heavy rains in some parts of the State. The matter is under consideration of the Central Government.